विदेशी तकनीकी जानकारी का आयात

9314. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में तकनीकी जानकारी के आयात के लिय भारत ने विभिन्न देशों को (देश-वार) कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य देशों से आयातित तकनीकी जानकारी समूचे देश की सम्पत्ति का अंग नहीं बनती अपितु किसी फर्म अथवा कम्पनी विशेष की सम्पत्ति बन जाती है जिसके परिणामस्वरूप उससे अपेक्षित लाभ नहीं उठाया जा सकता ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न कम्पनियां किसी विशेष प्रकार की तकनीकी जानकारी के लिए रायल्टी दे रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक ऐसी नीति बनाने का है जिसके अनुसार विदेशों से आयातित तकनीकी जानकारी किसी फर्म विशेष की निजी सम्पत्ति न बन जाये बल्कि वह समस्त राष्ट्र की सम्पत्ति बने ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) सभा पटल पर रखा जाता है । ग्रन्थालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT 3477/70]

(ख) और (घ). सामान्यत: भारतीय फर्मों द्वारा प्राप्त विदेशी तकनीकी जानकारी उसी फर्म की होती है जिसने इसे खरीदा है । हां, सरकार इस बात का सुनिश्चय करना चाहती है कि करार में एसी व्यवस्था है कि विदेशी सहयोगकर्त्ता सहित सभी संबंधित पार्टियों द्वारा आपस में सहमत शर्तों और उपबन्धों के अनुसार जो कि सरकार की स्वीकृति अधीन होती है यह आवश्यक होना चाहिए कि अन्य भारतीय पार्टियों को ऐसी तकनीकी जानकारी के लिए उप लाइसेंस दिये जा सकें ।

(ग) जी, हां । पहले ऐसे कुछ मामले हुए हैं जिसमें विभिन्न भारतीय फर्मों को उसी या उसी किस्म की निर्मित की जाने वाली वस्तु के लिए तकनीकी जानकारी के आयात की अनुमति दी गई थी । हां, ऐसे सभी मामले उसी समय पर मंजूर नहीं किये गये थे । फिर भी बार-बार ऐसी टेकनालाजी (प्रौद्योगिकी) के आयात को रोकने के विचार से, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विदेशी पार्टियों के साथ समन्वित आधार पर बात चीत की जानी चाहिए जबकि देश में उसी वस्तु के निर्माण के लिये उसी समय काफी संख्या में नए एककों को स्थापित करने का विचार हो ।

RECOVERY OF RENT FROM STAFF UNAUTHORISEDLY OCCUPYING FLATS IN RAILWAY COLONY, KHURDA ROAD (SOUTH-EASTERN RAILWAY)

9315. SHRI S. KUNDU : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1816 on the 30th July, 1968 regarding multistoreyed buildings at Khurda Road Railway colony and state :

(a) how much rent Government have recovered from the staff who had unauthorised occupied the flats in the Khurda Road Railway Colony of the South Eastern Railway;

(b) whether while realising such penal rent, a discrimination had been made among the employees and whether any such specific allegation has come to the notice of the Railway authorities particularly of the Divisional Superintendent, Khurda Road and, if so, the main points of such allegations and what steps have been taken to undo the wrong;

(c) whether any responsibility has been fixed against the officers for non-allotment of multistoreyed building at the Khurda Road Colony and, if so, the progress of such proceedings; and